

मप्र में मंगुभाई पटेल के नए कार्यकाल को लेकर संशय

**कन्हैया लोधी**

भोपाल, 27 जून. मप्र के मौजूदा राज्यपाल मंगुभाई पटेल का मौजूदा कार्यकाल 7 जुलाई को पूरा हो जाएगा. ऐसे में अब मप्र के नए राज्यपाल को लेकर अटकलें लगने लगी हैं. पटेल 8 जुलाई 2021 को मप्र के राज्यपाल बने थे, तब से लेकर अब तक वे लगातार प्रदेश के राज्यपाल बने हुए हैं. 7 जुलाई को उन्हें बतौर राज्यपाल पांच वर्ष पूरे हो जाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले वे मप्र के सातवें राज्यपाल होंगे.

उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक मौजूदा स्थिति में राज्यपाल के कार्यकाल को विस्तार दिये जाने की संभावना नहीं है. उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी उम्र को बताया जा रहा है. राज्यपाल पटेल ने इसी माह 82 वर्ष की आयु पूरी कर ली है. किसी भी व्यक्ति के लिए इस उम्र में बड़े संवैधानिक दायित्वों का

ट्राइबल सेल के लिए जाने जाएंगे मंगुभाई पटेल

मंगुभाई पटेल को बेहद सुलझे हुए राज्यपाल के रूप में जाना जाता है, व्यवहार कुशल, नम्र और म्रदु व्यवहार उनकी पहचान है, लेकिन मप्र के राज्यपाल बनने के बाद वे नए नवाचार के लिए भी जाने जाएंगे. सबसे बड़ी बात उन्होंने राजभवन में अलग से ट्राइबल सेल की स्थापना की. उनकी निगरानी में ये सेल प्रदेश में जनजाति समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की लगातार मॉनीटरिंग करती है. इस सेल का दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी दीपक खांडेकर को दिया गया है.

निर्वहन करना आसान नहीं होगा.

ऐसे में केवल नए राज्यपाल की नियुक्ति तक ही उनके विस्तार मिल सकता है या फिर उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मप्र के लिए राज्यपाल की नियुक्ति जा सकती है. संभावना जताई जा रही है कि मप्र को जुलाई में ही नए राज्यपाल मिल सकते हैं. मप्र के पिछले आधा दर्जन राज्यपाल को देखें तो गुजरात, उत्तरप्रदेश, पंजाब और दिल्ली का दबदबा रहा है. इस बार ये परिपाटी टूटने की संभावना जताई जा रही है. यानी अब जो भी राज्यपाल मिलेगा, वह कम से कम इन राज्यों से नहीं होगा.

रामनरेश यादव के बाद पांच वर्ष

का कार्यकाल पूरा करने वाले

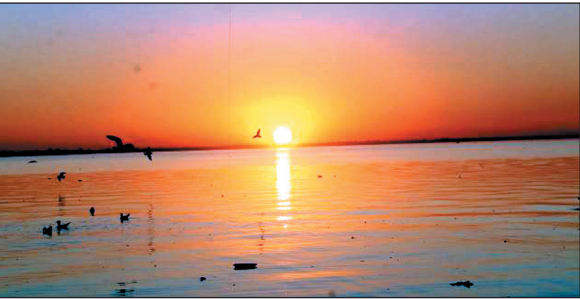
दूसरे राज्यपाल होंगे पटेल

मंगुभाई पटेल पिछले एक दशक बाद राज्यपाल का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे राज्यपाल होंगे. रामनरेश यादव आखिरी राज्यपाल थे, जिन्होंने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था. उम्र से आने वाले यादव को 8 सितंबर 2011 को राज्यपाल बनाया गया था और वे 11 जुलाई 2016 तक मप्र के राज्यपाल बने रहे. उनके

मप्र में अब तक मंगुभाई पटेल को मिलाकर कुल 30 राज्यपाल की नियुक्ति की गई है. तब से लेकर अब तक पटेल को मिलाकर महज सात राज्यपाल ही पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में कामयाब हुए हैं. इनमें हरितिनारायण पाटस्कर सबसे अधिक समय तक मप्र के राज्यपाल रहे हैं. उन्हें 14 जून 1957 को राज्यपाल बनाया गया था और वे 10 फरवरी 1965 तक राज्यपाल बने रहे थे. इस तरह वे सात वर्ष सात माह तक मप्र के राज्यपाल बने रहे. इनके अलावा केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, भाई महावीर, बलराम जाखड़ और रामनरेश यादव ने कार्यकाल पूरा किया.

बाद मप्र में ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन और एक बार फिर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया. अब मंगुभाई पटेल ही ये कार्यकाल पूरा करने की दहलीज पर पहुंच गए हैं.

मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी



भोपाल, 27 जून. मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है. 15 जिलों में प्रवेश के बाद पिछले तीन दिनों से मानसून आगे नहीं बढ़ सका है, हालांकि बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 43 जिलों में बारिश का अलर्ट शनिवार को जारी किया है.

43 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अनुकूल परिस्थितियां बनने पर मानसून के फिर से सक्रिय होने और भोपाल-उज्जैन संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. ग्वालियर-चंबल अंचल में मानसून की दस्तक

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, सीहोर, विदिशा, धार, खंडवा, खरगोन सहित कुल 43 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति रह सकती है. बारिश के चलते प्रदेश के अधिकतर शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है.

सबसे आखिर में होने का अनुमान है. 24 जून को मानसून ने प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में प्रवेश किया था.

रीवा का सुंदरजा आम अब यू.ए.ई. पहुंचा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 जून. रीवा का सुंदरजा आम अब वैश्विक बाजारों की शान बन गया है. केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के सहयोग से जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आम मप्र से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पहले वाणिज्यिक निर्यात के रूप में पहुंच गये हैं. पिछले कई महीनों से एपीडा ने मप्र सरकार के बागवानी विभाग, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ, पैकिंग हाउस संचालकों और

अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट किस्म के आम के निर्यात के लिए संपर्क स्थापित करने का काम किया है. इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब अमीरात में एक खरीदार की पहचान हुई जिससे प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम के अंतर्राष्ट्रीय विपणन का मार्ग खुला. जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात खेप में एक मीट्रिक टन आम शामिल थे और यह 26 जून को मेसर्स साल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई.

एक नजर में

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत
अनूपपुर. जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुंटाटोला-डोंगरिया मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांचशुरू कर दी है. जैतहरी पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है.

खौलता पानी पीने को मजबूर मरीज

सिंगरौली. जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैदून की व्यवस्थाएं फिर से बेपटरी पर आ गई हैं. आलम यह है कि सेकेंड फ्लोर में स्थित अधिकांश वार्डों में पानी एवं पंखे जहां खराब हैं, वहीं एक कूलर के सहारे मरीज काम चला रहे हैं. इधर मरीजों को पीने के लिए टंडपानी नसीब नहीं हो रहा है. दरसाल जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर बैदून फिर से अव्यवस्थाओं में घिरने लगा है. आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में मरीजों को वाटर कूलर पानी टंड के बदले खौलता पानी दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह समस्या कई दिनों से है, लेकिन जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर प्रबंधन अनजान बना हुआ है. मरीजों एवं अस्पताल में आने वाले लोगों को खौलता पानी नसीब हो रहा है. वहीं सेकेंड फ्लोर के मेल वार्ड के एसी व पंखे बंद पड़ी हुई हैं और कहीं-कहीं एक कूलर भी लगे हुये हैं.

पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग उठी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जून . मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेट्री ने शनिवार को राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा एवं भर्ती में व्यापक सुधारों की मांग की.

संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और जयवर्धन सिंह ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्यव्यापी जनजागरण अभियान की घोषणा की. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि लगातार भर्ती घोटालों और परीक्षा संबंधी विवादों से



छात्रों एवं नौकरी के अभ्यर्थियों का भरोसा टूट गया है. उन्होंने कहा कि व्यापम से लेकर हालिया भर्ती और नर्सिंग परीक्षा मामलों तक प्रदेश में परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में रही है. उन्होंने सरकार पर लगभग 4.87 लाख रिक्त पद नहीं भरने का आरोप लगाते हुए वाणिज्य भर्ती कैलेंडर, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और सभी परीक्षाओं के लिए एकमुश्त शुल्क व्यवस्था लागू करने की

मांग की. जयवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का विश्वास कमजोर किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता-जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई.

वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) ईश्वर जराडे और उपवनमंडल अधिकारी एमडी मानिकपुरी के निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने 26 जून 2026 को ग्राम बांसनी स्थित आरोपियों के घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक कमरे से बर्तन व डिब्बों में रखा हुआ पका, उबला व भुना हुआ मांस बरामद किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने

पेज एक का शेष

युवा जोश के साथ बहुजन विचार का फार्मूला

कड़ाई से लागू किया जा रहा है. पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में सभी 60 सदस्यों और प्रभारियों के साथ मेराशन बैठक की थी. उस बैठक का उद्देश्य साफ था कि पिछले छह महीनों का लिखित रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी और उसी आधार पर उनका भविष्य तय होगा. उस बैठक के बाद से ही कहा जा रहा था कि लगभग

योगी का बेटियों को शिक्षा तोहफा

यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्वतंत्रपोषित विद्यालयों में कक्षा नी से 12 तक विद्यार्थियों से ली जा रही टयूशन फीस का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस आंकड़े के आधार पर योजना का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों की दूसरी बेटी को फीस में राहत का लाभ मिल सके.

पेज तीन का शेष

सरकार ने बांटे 1,274 करोड़

और मंडला के उद्यमियों से संवाद भी किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 41 हजार से अधिक एमएसएमई यूनिट्स की कमान माताओं-बहनों के हाथों में है।गत वर्षों के मुक़ाबले वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व 59 प्रतिशत बढ़ा है. राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 16 कलस्टर निर्माण किया है और 14 नए कलस्टर पर काम चल रहा है. राज्य सरकार ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया है. साथ ही वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है.

महा आयोजन

समितियों में सेवानिवृत्तों को भी करेंगे शामिल



नवभारत न्यूज़
उज्जैन, 27 जून. वर्ष 1980 के सिंहस्थ से बात शुरू करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि किसी न किसी रूप में सिंहस्थ के आयोजनों से जुड़ा रहा हूं, यह महाकाल की कृपा है कि उज्जैन के बाशिंदे को सत्ता के शिखर पर पदस्थ किया और आप भी महाकाल की कृपा से ही उज्जैन में पदस्थ रहे हो ऐसे में बीते सिंहस्थ के जो अनुभव लिए हैं उसे आने वाले

शनिवार को उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हर 12 साल में होने वाला सिंहस्थ भारत की ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है. यह हमारी अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति, दर्शन, पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, अटूट आस्था और हमारी आध्यात्मिक परम्पराओं का महासंगम है. इस धार्मिक उत्सव में मां शिखा के जल में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है. सिंहस्थ-2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर हुई एक वृहद प्रशिक्षण कार्यशाला को सीएम ने संबोधित किया.सिंहस्थ

मंत्रालय के गलियारे से

एसीएस का एआई प्रेम

कन्हैया लोधी

सांसद और विधायक की जुगलबंदी

पिछले दिनों मंत्रालय में एक सांसद और विधायक की जुगलबंदी चर्चा का विषय बनी रही . ये दोनों ही

नेता एक साथ मंत्रालय में कदमताल करते नजर आए . पहले तो किसी बात को लेकर सरकार के पास गए, फिर वे एक बड़े अफसर के

पास पहुंचे . बड़े साहब भी पूरे मूड में थे, उन्होंने पूरे इत्मीनान से दोनों की बातें सुनीं और भरोसा दिलाया कि ऑल इज वेल . वैसे इन दोनों को ही एक एक केंद्रीय मंत्री के खेमे का माना जाता है . राजनीतिक अभ्युदय में उनका बड़ा रोल रहा है . सांसद को टिकट दिलाने में केंद्रीय मंत्री की बड़ी भूमिका मानी जाती है . वैसे राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता . बहरहाल इसे निशा परिवर्तन से जोड़कर भी देखा जा रहा है .

...और पूर्व मंत्री को केवल आश्वासन ही मिल सका

वैसे तो अब विभागीय रूटीन ट्रांसफर पर रोक लग गई है, ट्रांसफर के सीजन में क्या आम और क्या खास, सब अपने और अपने के ट्रांसफर के लिए परेशान दिखे . इसी क्रम में एक प्रमुख सचिव के कक्ष में एक पूर्व राज्य मंत्री पहुंचे . वे अपने किसी आत्मीय जन के ट्रांसफर के लिए पीएस से अनुरोध कर रहे थे, लेकिन पीएस ने भी उन्हें प्रक्रिया और पद रिक्त नहीं होने के फेर में ऐसे उलझाया कि पूर्व राज्यमंत्री को केवल आश्वासन ही मिल सका .

विधायक का शक्ति संतुलन

प्रदेश की एक विधायक के शक्ति संतुलन की जबर्दस्त चर्चा है . विधायक महोदया ने तो भाजपा में है और न ही कांग्रेस में है . तकनीकी रूप से वे कांग्रेस के साथ दिखती हैं, लेकिन भौतिक रूप से भाजपा के साथ, अब कोई उन्हें अपना माने भी तो कैसे . इधर कांग्रेस को उनके मामले में कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है . ऐसे में विधायक महोदया को दोनों ही दलों को उलझाने का और मौका मिल गया है . इसी उलझान में आधा कार्यकाल बीत गया है, अब देखते हैं, बाकी कार्यकाल कब तक ऐसे ही निकलता है .

हत्या मामले में फरार चल रहा इनामी आरोपी पकड़ाया

भिण्ड 27 जून. भिण्ड जिले के मेहगांव थाना पुलिस ने कैथोला गांव में हुए चर्चित हत्याकांड के एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है. इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस के अनुसार गत 20 अप्रैल को कैथोला गांव निवासी गिर्राज गुर्जर गांव में न्यूला (भोज)

खाकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी, डंडों व बंदूक से हमला कर दिया.

मारपीट के बाद गिर्राज गुर्जर को गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मामले में मेहगांव थाना पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी. जांच में पुलिस ने आसवीर गुर्जर, नाथ गुर्जर और साहब सिंह गुर्जर को आरोपी बनाया था.

मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप करें समाप्त

मंदिरों की आय पर सरकार का अधिकार नहीं : शंकराचार्य



मंदिरों में दान और चढ़ावे के रूप में करोड़ों रुपये की आय होती है. मंदिरों के नियमित खर्च के बाद बचने वाली राशि का उपयोग उसी क्षेत्र के विकास में किया जाना चाहिए, जहां मंदिर स्थित है.

उन्होंने सुझाव दिया कि इस राशि से अस्पताल, पाशालाएं,

शंकराचार्य ने कहा कि मंदिरों का धन किसी अन्य उद्देश्य पर खर्च नहीं होना चाहिए . धार्मिक संस्थाएं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और उनकी आय का उपयोग जनकल्याण के लिए ही होना चाहिए . साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में दोषियों को कठोर सजा देने की मांग भी की .

धर्मशालाएं, गौशालाएं और संस्कृत विद्यालय जैसे जनहित के कार्य संचालित किए जाएं, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिल सके.